

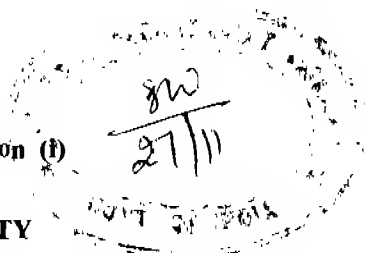


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 395]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 1989/श्रावण 9, 1911

No. 395] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 1989/SRAVANA 9, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विदेश मंत्रालय

(विधि एवं संधि प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1989

मा.का.नि. 721(अ) :—जबकि यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड की महामहिम सहायनी, भारत की सम्राज्ञी, और नोर्वे-लैण्ड की महामहिम सहायनी के बीच अणुशक्ति के प्रसारण के लिए 26 सितम्बर, 1898 की संधि और 14 दिसम्बर, 1898 को लन्दन में जिसके अनुसमर्थन कस्तावेजों का आशय-प्रदान हुआ, निम्नलिखित का उद्देश्य करती है :—

“अनुच्छेद-एक—उपर्युक्त उच्च संविदाकारी पक्ष इस बात पर सहमत होते हैं कि वे वर्तमान संधि में निहित परिस्थितियों और शर्तों के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को एक-दूसरे का सौंदर्य देने जिस पर किसी एक पक्ष के प्रदेश में कोई अपराध था जून करने का अभियोग लगाया गया है अथवा उनका दाय सिद्ध हो चुका हो और वह दूसरे पक्ष के प्रदेश में पकड़ा गया हो।

अनुच्छेद-दो—जिन अपराधों या जुर्मों के लिए प्रत्यार्थन किया जा सकेगा वे नीचे लिखे अनुसार हैं :—

1. हत्या, जिसमें बल-हत्या शामिल है, या हत्या का प्रयत्न या हत्या का षडयंत्र, जिसमें वे अपराध भी शामिल हैं जो संलग्नतामय अपराध

2119 GI/89

उभके उत्तराधिकारी या किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए हों, बतान कि वह अपराध राजनीतिक स्वरूप का न हो।

2. नर-हत्या जिसमें बच्चे की नर-हत्या शामिल है।

3. हमला, जिसमें बलपूर्वक शारीरिक क्षति पहुँची हो।

4. दुर्भावपूर्णक जहनी करना या संसार शारीरिक क्षति पहुँचाना।

5. मुद्रा को जालसाजी या हेरा-फेरा अथवा ऐसी भावों या हेरा-फेरा को हुई मुद्रा का प्रयोग।

6. घोखा-धड़ी, जाल साजी या हेरा-फेरा या जो जाबजा-दो में या जालसाजी या हेरा-फेरा का गई कर्तु को बताना।

7. भवन, किसी उप निद्रिणी क्षेत्र, एजेंट, आइडिफा, समी अथवा किसी कम्पनी के निर्देशक या सदस्य या जो अधिकारी द्वारा की गई घोखाधड़ी जो उन समय लागू हिवा भा कानून के अन्तर्गत आतशायिता रहस्य गथा हो अथवा चीरो।

8. सम्पत्ति को दुर्भावपूर्ण क्षति यदि अपराध प्रमाणित हो।

9. किंगो बहाने में धन, माल या नृत्वान प्रतिभूतियां ले लेना।

10. दिवंगतिया कानून के अन्तर्गत अपराध।

11. भिक्षा, मदद देना या भिक्षा मांगने के लिए प्रेरित करना।

12. उपाधकार।

(1)

13. 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ मैथुन या मैथुन कायल।

14. किसी के साथ प्रणीत व्यसहार।

15. किसी महिला के गर्भपात कराने के उद्देश्य से औषधि खिलाता-पिलाता या शीशरों का प्रयोग करना।

16. अपहरण।

17. बच्चा चुराना।

18. नाबालिगों का अपहरण और उन्हें गलत ढंग से वंशी बनाकर रखना।

19. संधमारी और बीरी से घर में घुसना।

20. आगजनी

21. हिंसात्मक झकड़ौ

22. रेलगाड़ी की सुरक्षा को खतरे में डालने से किया गया कोई भी दुर्मायनापूर्ण कार्य।

23. घन ऐंठने के द्वारा से पत्र द्वारा या किसी अन्य तरीके से घम-किया देना।

24. अन्तर्राष्ट्रीय विधि को अधीन जलवस्तुता।

25. समुद्र में किसी पोत को डुबाना या नष्ट करना या ऐसा करने का प्रयत्न करना।

26. किसी को मारने या नुशीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के द्वारा से खुले समुद्र में जहाज में सवारों पर हमले करना।

27. खुले समुद्रों में जहाज पर सवारों या वे से अधिक व्यक्तियों द्वारा जहाज के स्वामी के प्राधिकार के विरुद्ध विद्रोह करना।

28. गुलानों का इस तरह व्यापार करना जो दोनों राज्यों के कानूनों के विरुद्ध बाह्य अपराध बनता हो।

उपरोक्त में से किसी भी अपराध में भाग लेने के लिए भी प्रत्यर्पण की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की भागीदारी उस देश के कानूनों के अनुसार प्रत्यर्पण का अपराध बनता हो जिसे इसके लिए आवेदन किया गया हो।

उक्त मामलों में प्रत्यर्पण तभी किया जाएगा जबकि सम्बद्ध अपराध यदि उस देश के अधिकार क्षेत्र में किया गया हो, जिससे प्रत्यर्पण करने की मांग की गयी है, उस देश के कानूनों के अनुसार प्रत्यर्पण अपराध बनता हो।

जिस राज्य से प्रत्यर्पण की मांग की गई हो, वह अगर चाहे तो किसी ऐसे अपराध के संबंध में भी प्रत्यर्पण की अनुमति दे सकता है जिनमें दोनों संधिदाकारी पक्षों के तत्कालीन कानूनों के अनुसार इसकी अनुमति दी जा सकती हो।

अनुच्छेद तीन—दोनों में से कोई भी सरकार पूर्णतः अपने विवेक में अपने प्रजाजनों की दूसरी सरकार को सौंपने से इंकार कर सकती है।

अनुच्छेद चार—अगर ब्रिटेन की सरकार जिस व्यक्ति को प्रत्यर्पण की मांग करे उस पर तीयरलैंड की सरकार जिस व्यक्ति की मांग करे उस पर दोनों उच्च संधिदाकारी पक्षों में से किसी एक के प्रदेश में उस अपराध के लिए पहले में ही मुकदमा चलाया जा चुका हो या उसके फलस्वरूप बरी कर दिया गया हो या दंडित किया गया हो या दाखल में उस पर मुकदमा चल रहा हो उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा।

यदि उस व्यक्ति के संबंध में, जिसकी मांग ब्रिटेन की सरकार को और ने की गयी हो या उस व्यक्ति के संबंध में, जिसकी मांग तीयरलैंड की सरकार को और से की गयी हो, ज्ञात पड़ता न हो रही हो या वह दोनों उच्च संधिदाकारी पक्षों के प्रदेशों के अन्दर किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर सजा सुना रहा हो तो उक्त प्रत्यर्पण तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक कि वह दोषी न करार दिया जाय या अपनी सजा की मियाद पूरी न करायें अन्यथा रिहा न कर दिया गया हो।

अनुच्छेद पांच—प्रत्यर्पण उस देश में भी नहीं किया जाएगा जब कि अपराध करने के बाव या बंड अनियोजित शुरू करने या उस परिणामस्वरूप दोष सिद्ध हो जाने के बाद निर्धारित गन्तव्य अथवा बाव का बखर्क से उस व्यक्ति को अनियोजित या बंड से उस राज्य के कानूनों के अनुसार छूट मिल गई हो, जिस राज्य से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो।

अनुच्छेद छह—किसी ऐसी प्रणाली अपराधी का गमगंन नहीं किया जाएगा यदि उसका अपराध जिसके संबंध में उसकी समर्पण की मांग की गई हो, राजनैतिक स्वभाव का हो या वह यह सिद्ध कर दे कि उसके समर्पण की मांग वास्तव में एक राजनैतिक स्वभाव के अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाने या सजा देने के लिए की गई है।

अनुच्छेद सात—समर्पित किसी व्यक्ति को किसी भी सूरत में जेल में नहीं रखा जाना चाहिए और न ही उस राज्य में जिस वह समर्पित किया गया हो उस अपराध या उन मामलों की छोड़कर किसी अन्य अपराध या किसी अन्य मामलों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए जिनके लिए उसका प्रत्यर्पण किया गया हो जब तक कि उसे उस राज्य का दावस न सौंप दिया गया हो जिसने उसका समर्पण किया है या यहाँ लौटने के बाद उसे एक महीने का मौका न मिल गया हो।

यह शर्त उन अपराधों पर लागू नहीं होगी जो प्रत्यर्पण के बाद किए गए हो अनुच्छेद आठ—प्रत्यर्पण का अनुरोध उच्च संधिदाकारी पक्षों के अपने राजनैतिक एजेंटों के माध्यम से किया जाएगा।

दायी व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग के साथ प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश के सक्षम प्राधिकारों द्वारा जारी किया गया लिखतारी हो वारंट होना चाहिए और ऐसे साथ ही साथ में होने चाहिए जिनसे प्रतिपक्ष के मिलने की जगह के कानून के अनुसार यह स्थापित ठहरता हो कि अगर वह वहाँ ऐसा अपराध करता तो वहाँ या उसे निराधार किया जाता।

यदि किसी ऐसे व्यक्ति के प्रत्यर्पण का मांग का गई हो जो पहले ही दोषी सिद्ध हो चुका हो तो अनुरोध के साथ उस देश के जो प्रत्यर्पण की मांग करता है, सक्षम स्थापत्य द्वारा दायां व्यक्ति के विरुद्ध जारी दण्डादेश होना चाहिए।

दुराग्रहपूर्वक दी गई किसी सजा का निवृत्त नहीं माना जाएगा बल्कि ऐसे स्थापत्य व्यक्ति के साथ एक अनिवार्य को तरह व्यवहार किया जाएगा।

अनुच्छेद नौ—यदि प्रत्यर्पण की मांग पूर्वोक्त शर्तों के प्रत्यक्ष है तो उस देश के जिसे आवेदन किया गया हो, सक्षम प्राधिकारों द्वारा व्यक्ति को निरन्तर करने की कार्यवाई करेगे।

अनुच्छेद दस—राजनैतिक माध्यम से प्रत्यर्पण के लिए मांग प्रस्तुत होने तक प्रणाली अपराधी को दोनों में से किसी एक देश में किसी पुलिस मजिस्ट्रेट जस्टिस प्राफ व पीस या अन्य सक्षम प्राधिकारों द्वारा ऐसी किसी सूचना या निष्कर्ष और ऐसे माध्यम के आधार पर या ऐसी कार्यवाई के बाद जिनसे वारंट जारी करने वाले प्राधिकारों का राय में वारंट जारी करने का औचित्य सिद्ध होता हो, जारी वारंट के अन्तर्गत

पकड़ा जा सकता है। यदि अपराध दोनों संविधिकारी पक्षों के राज्य के हम भाग में किया गया हो या वह व्यक्ति उसमें दोनों संविधिकारी हों जो मजिस्ट्रेट, जजिस्ट्र और द फोर्स या अन्य सक्षम प्राधिकारी का अधिकार-क्षेत्र हो। लेकिन ध्यान यह है कि प्रत्येक को यूनाइटेड किंगडम में, ऐसे मामले में, मजिस्ट्रेट के समक्ष बयानोब प्रस्तुत किया जाएगा। उसे इस अनुच्छेद के अनुसार नोडरलैण्ड में तथा यूनाइटेड किंगडम में भी मुक्त कर दिया जाएगा, यदि प्रत्येक की मांग 20 दिन की अवधि के अन्दर इस संधि की शर्तों के अनुरूप मांगकर्ता देश के राजनयिक एजेंट द्वारा की गई हो। सही निम्न उन व्यक्तियों के मामले में भी लागू होगा जिनके बीच संधि में बताये गए किसी अपराध या जुन का प्रत्येक लगाया गया हो दोषी पाया गया हो और यह अपराध उन्होंने दोनों में से किसी भी देश के अदालत पर खड़े समुद्र में किया हो और जहाज देश के दूसरे देश के पत्तन पर पहुंच गया हो।

अनुच्छेद बारह—यदि अपराधी ब्रिटेन के किसी अधिराज्य में गिरफ्तार किया गया है तो उसे तत्काल सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा जो उसकी जांच करेगा और इस मामले में प्रारम्भिक पूछताछ ठीक वैसे ही करेगा, माना उसे ब्रिटेन के अधिकार-क्षेत्र में किए गए अपराध के लिए पकड़ा गया हो।

जांच में, जो उन्हें पूर्वोक्त शर्तों के अनुरूप करना है, ब्रिटिश अधिराज्य के प्राधिकारी शपथ पर दिए गए अभिसाध्य या नोडरलैण्ड में ली गई गवाही के अभिसाध्यों या कथनों या उनकी प्रतियों और इसी प्रकार उसमें जारी वारंट और सजा और दोष सिद्ध करने के प्रमाण पत्र या न्यायिक दस्तावेज जिनमें उसके तथ्य बताए गए हों, को वैध साक्ष्य स्वीकार करेंगे बशर्ते कि वे नीचे लिखे अनुसार प्रमाणित किए गए हों :—

1. कोई वारंट जिसके बारे में यह माना जाए कि नोडरलैण्ड के किसी जज, मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

2. अभिसाध्यों अथवा प्रतिज्ञापत्रों या उसकी प्रतियों के बारे में यह निश्चय होना चाहिए कि वे नोडरलैण्ड के किसी जज, मजिस्ट्रेट या किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गए हैं या वे मूल अभिसाध्य या प्रतिज्ञापत्र या उनकी सत्य प्रतिलिपियां हैं जैसा भी व्यक्ति के अनुरूप आवश्यक हो।

3. ऐसे किसी प्रमाण-पत्र या न्यायिक दस्तावेज से, जिसमें सिद्ध दाव का तथ्य वर्णित हो, यह प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि नोडरलैण्ड के किसी जज, मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

4. प्रत्येक मामले में ऐसे वारंट अभिसाध्य, प्रतिज्ञापत्र, प्रति, प्रमाण-पत्र या न्यायिक दस्तावेज किसी गवाह की शपथ द्वारा या नोडरलैण्ड के न्याय मंत्री या किसी अन्य राज्य मंत्री की सरकारी मोहूर से मुहरबंद करके अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए; परन्तु ब्रिटेन के अधिराज्य के ऐसे किसी भाग में, जहां जांच की जानी है लागू कानून द्वारा फिलहाल अनुमत अधिप्रमाणन के किसी अन्य तरीके को पूर्वोक्त तरीके के स्थान पर अपनाया जा सकता है।

अनुच्छेद बारह—यदि प्रचाली नोडरलैण्ड के अधिराज्य में पकड़ा गया है तो न्याय अधिकारी गिरफ्तारी के तीन दिन के अन्दर उसे हाजिर होने के लिए कहेगा या यदि गिरफ्तारी नहीं की गई है या यदि गिरफ्तारी प्रत्येक के लिए आवश्यक करने से पहले हुई है तो नोडरलैण्ड की सरकार से उस उद्देश्य के लिए प्राधिकार की प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर उसे हाजिर होने के लिए कहेगा ताकि उस व्यक्ति से, जिसके प्रत्येक की मांग की गयी है, न्यायालय पूछताछ कर सके और वह प्रत्येक की अनुमति देने या इसे अस्वीकार करने के संबंध में अपनी राय व्यक्त कर सके। पूछताछ के 14 दिन के अन्दर न्यायालय उस मामले के कामकाजों सहित अपनी राय और निर्णय न्याय मंत्री को भेज देगा।

प्रत्येक की अनुमति निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप में या उसकी अधिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी।

1. सिद्ध दोष की; या

2. (क) गिरफ्तारी के वारंट की (जो ब्रिटेन के अधिराज्य के कानून के अनुसार एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जो उस मामले में लिया जाता है जहां शपथ पर दिए गए दाव पर वह दस्तावेज सिद्ध हो जाए कि अभियुक्त को अदालत में लिया जाना चाहिए) जो ब्रिटेन के कानून द्वारा निर्धारित फॉर्म में जारी किया जाना चाहिए और जिसमें प्रत्येक अपराध पर्याप्त रूप से बताया जाता चाहिए ताकि नोडरलैण्ड की सरकार यह निर्णय ले सके कि हमने नोडरलैण्ड के कानून के अनुसार एक ऐसा मामला बनवा है जिसका व्यवस्था वर्तमान संधि में की गई है, और

(ख) नाक्ष्य की।

जांच में जो उन्हें पूर्वोक्त शर्तों के अनुरूप करना है, नोडरलैण्ड अधिराज्य के प्राधिकारी शपथ पर दी गई अभिसाधियों या कथनों या ब्रिटिश अधिराज्य में ली गई गवाही के अभिसाध्यों या कथनों या उनकी प्रतियों और इसी प्रकार उसमें जारी वारंट और सजा और दोष सिद्ध करने के प्रमाण-पत्र या न्यायिक दस्तावेज जिनमें उसके तथ्य बताए गए हों, को वैध साक्ष्य स्वीकार करेंगे बशर्ते कि वे नीचे लिखे अनुसार प्रमाणित किए गए हों :—

1. कोई वारंट जिसके बारे में यह माना जाए कि उस पर ब्रिटिश अधिराज्य के किसी जज, मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

2. अभिसाध्यों अथवा प्रतिज्ञापत्रों या उनकी प्रतियों के बारे में यह निश्चय होना चाहिए कि वे ब्रिटिश अधिराज्य के किसी जज, मजिस्ट्रेट या किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए हैं या वे मूल अभिसाध्य या प्रतिज्ञापत्र या उनकी सत्य प्रतिलिपियां हैं जैसी भी स्थिति के अनुरूप आवश्यक हो।

3. ऐसे किसी प्रमाण-पत्र या न्यायिक दस्तावेज से जिसमें सिद्ध दोष का तथ्य वर्णित हो, यह प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि वह ब्रिटिश अधिराज्य के किसी जज, मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

4. प्रत्येक मामले में ऐसे वारंट, अभिसाध्य, प्रतिज्ञापत्र, प्रति, प्रमाण-पत्र या न्यायिक दस्तावेज किसी गवाह की शपथ द्वारा या ब्रिटिश अधिराज्य के किसी प्रमुख विदेश मंत्री या किसी अन्य राज्य मंत्री की सरकारी मोहूर से मुहरबंद करके अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए; परन्तु नोडरलैण्ड के अधिराज्य के ऐसे किसी भाग में, जहां जांच की जानी है, लागू कानून द्वारा फिलहाल अनुमत अधिप्रमाणन के किसी अन्य तरीके को पूर्वोक्त तरीके के स्थान पर अपनाया जा सकता है।

अनुच्छेद तेरह—प्रत्येक तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि राक्षस उस देश के कानूनों के अनुसार पर्याप्त न पाया जाए जहां आवश्यक किया गया है, जो यदि अपराध उस देश के क्षेत्र में किया गया है तो बंदी पर मुदतमा खवाया जाने के लिए उनकी सुपुर्दगी उचित दहरान के लिए या यह सिद्ध करने के लिए होगा कि किसी वही व्यक्ति है जिसे उस देश के न्यायालयों ने बोला ठहराया है जिसने प्रत्येक की मांग की है और यह कि वह अपराध, जिसके लिए उसे बोला सिद्ध किया गया है एक ऐसा अपराध है जिसके संबंध में प्रत्येक अनुमति ऐसी दोष सिद्धि के समय उस देश द्वारा दी जा सकती था जिसे आवश्यक किया गया है। अपराधी अपराधी को तब तक नहीं मंगा जाएगा जब तक कि उसकी सुपुर्दगी की प्रतीक्षा के लिए उसे बंदी धराए जाने की भारीख से 15 दिन की अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

अनुच्छेद चौदह—यदि वर्तमान संधि के अन्तर्गत दोनों उच्च संविधिकारी पक्षों में से कोई एक संविधिकारी पक्ष किसी ऐसे व्यक्ति के प्रत्येक की मांग करता है और उस व्यक्ति के किसी एक या कई अन्य व्यक्तियों ने उस व्यक्ति द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए अन्य अपराधों के लिए

लिए एक प्रत्यर्पण की मांग की हो तो उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण उग देश को दिया जाएगा जिसने पहले मांग की हो।

अनुच्छेद-पंद्रह—गुप्त किए जाने वाले व्यक्ति का गिरफ्तारी के समय या गमन उसके पास था, वह यदि, उस देश के, जिस प्रत्यर्पण के लिए आवेदन किया गया है, मक्षम प्राधिकारी ने उसके प्रेषण के आदेश दिए हैं तो प्रत्यर्पण के समय दिया जाएगा और भिन्न चुनया हुआ गमन ही नहीं बल्कि हर ऐसी हर चीज दे दी जाएगी जिससे उमरा अपराध प्रमाणित हो सकता है।

अनुच्छेद-सातह—दोनों सरकारें परस्पर यह घोषणा करती हैं कि गुप्त किए जाने वाले व्यक्ति का गिरफ्तार करने, उसे खिलान-पिलाने और उसके परिवहन पर जो खर्च आएगा उसके भुगतान का बोझ नहीं करेंगी और उन तमाम खर्चों का भी जो उन्हें गुप्त किए जाने वाले व्यक्ति को जहाज में बैठाने तक अपने-अपने प्रदेशों की सीमा में करना होगा नहीं-वे जहां की गद्दी चीजों को देने या लौटाने पर खर्च लेते हैं जिनमें उन गमन जात का भोजना और वापस करना भी शामिल है जिनमें अपराध का प्रमाण हो और ऐसे ही दूसरे दस्तावेज भी; और वे परस्पर इस पर बात सहमत हैं कि वे ऐसी सभी खर्च खुद ही उठाएंगे।

लेकिन उक्त अनुबन्ध कनाडा को और वहां से हाने वाली प्रत्यर्पण पर लागू नहीं होंगे, जहां तब इस कालोनी का संबंध है सभी खर्च मानवता राज्य द्वारा वहन किए जाएंगे।

प्रत्यर्पण के अर्थात् व्यक्ति को मांगकर्ता राज्य के राजनयिक या कोमरी एजेंट द्वारा इंग्लैंड बंदरगाह पर पहुंचाया जाएगा।

अनुच्छेद-सत्रह—यदि दोनों देशों में से किसी एक के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में कोई फौजदारी मामला चल रहा है और उसके मामले में दूसरे के देश में किसी गवाहों का साक्ष्य लेना बालनीय समझा जाए तो जिस देश में वह गवाह हो वहां इस विषय पर लागू कानूनों के अनुसार वहां के न्यायिक अधिकारी इस कानूनों के अनुसार इस प्रकार का साक्ष्य ले सकते हैं और इस प्रकार का साक्ष्य लेने में जो खर्च आएगा उसे वह देश भरा करेगा जिसमें यह साक्ष्य लिया गया हो।

अनुच्छेद-अठारह—वर्तमान संधि के अनुबन्ध दोनों उच्च सेविदाकारी पक्षों की कालोनियों और इनके अर्थात् विदेशी क्षेत्रों पर लागू होंगे, लेकिन चूंकि ये अनुबन्ध मानदंड के कानून पर आधारित है इसलिए इसका पालन दोनों आर में उतना ही किया जाएगा जितने की वे इन कालोनियों या अधिकृत क्षेत्रों में लागू कानूनों से मिल सकते हैं।

जिस अपराधों के प्रत्यर्पण की मांग, जिनमें किसी भी एक सेविदाकारी पक्ष की कालोनी या विदेशी अधिकृत क्षेत्र में शरण ली है, संधि उस कालोनी या अधिकृत क्षेत्र के गवर्नर या प्रमुख अधिकारी को दूसरे सेविदाकारी पक्ष के एक कालोनी या अधिकृत क्षेत्र के गवर्नर या प्रमुख अधिकारी द्वारा भी की जा सकती है अब दो कालोनियों या विदेशी अधिकृत क्षेत्र एशिया, आस्ट्रेलिया (जिनमें न्यूजीलैंड और सामोनिया शामिल हैं) प्रशान्त और हिन्द महासागर या दक्षिण या पूर्वी अफ्रीका में स्थित हों।

यदि दो कालोनियों विदेशी अधिकृत क्षेत्र अमेरिका (जिनमें सेंट इडिया द्वीप समूह शामिल हैं) में स्थित हों तो इसी नियम का अनुसरण किया जाएगा।

उक्त गवर्नरों या प्रमुख अधिकारियों का यह अधिकार होगा कि वे प्रत्यर्पण की अनुमति दे या अपनी सरकार को इस मामले को भेज दें।

श्रव्य सभी मामलों में प्रत्यर्पण की मांग राजनयिक माध्यमों से की जाएगी।

अस्थायी गिरफ्तारी की अवधि जैसी कि अनुच्छेद दश में व्यवस्था है, इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए 60 दिन कर दी जाएगी।

अनुच्छेद-उत्तम—त्रिग दिन से यह संधि लागू हो जाएगी उसी दिन से दोनों देशों के बीच 19 जून 1871 को सम्पन्न प्रत्यर्पण संधि निष्प्रभावी हो जाएगी परन्तु वर्तमान संधि इस संधि के अन्तर्गत आने वाले सभी अपराधों पर लागू होंगी चाहे वे इसके लागू होने के दिन से पहले या बाद में किए गए हों।

अनुच्छेद-दशह—वर्तमान संधि अनुमार्जन के अर्थात् हांगी और अनु-मार्जन के दस्तावेजों का प्रशासीय आदान-प्रदान किया जाएगा।

यह संधि अनुमार्जन के दस्तावेजों के आदान-प्रदानों के तीन महीने बाद लागू होगी। कोई भी उच्च सेविदाकारी पक्ष किसी भी समय इसे समाप्त करने के अपने इरादे को सूचना दूसरे पक्ष को छह महीने पहले देकर समाप्त कर सकता है।

जिनके साक्ष्य में दोनों देशों के अपने-अपने पूर्वविकारियों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और इसपर अपना-अपना मुद्रा लगाया है।

लंदन में आज 1898 के विनम्बर मास के छठीसब दिन का प्रतियों में सम्पन्न हुई।

अतः, अत्र, केन्द्र सरकार प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) को धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध अध्याय 3 का खंडक, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख की ओर उससे तीदरलैडस को लागू होंगे।

[सं.एच./413/13/88]

डा. वि. श्रीनिवासन राव, निदेशक (वि.एच.सं.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Legal & Treaties Division)

ORDER

New Delhi, the 28th July, 1989

G.S.R. 721(E).--Whereas the treaty between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India, and Her Majesty the Queen of the Netherlands, for the extradition of criminals, dated 26th day of September 1898 and ratifications exchanged at London, on December 14, 1898, provides as follows:—
"Article-I

"The High Contracting Parties engage to deliver up to each other those persons who, being accused or convicted of a crime or offence committed in the territory of the one Party, shall be found within the territory of the other Party, under the circumstances and conditions stated in the present Treaty.

11. The crimes or offences for which the extradition is to be granted are the following:

1. Murder, including infanticide, or attempt, or conspiracy to murder, including such crimes when directed against the Sovereign, his heir, or any other person whomsoever, provided that the crime is not of a political character.
2. Manslaughter, including the manslaughter of a child
3. Assault occasioning actual bodily harm.
4. Maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm.
5. Counterfeiting or altering money, or uttering counterfeit or altered money.
6. Forgery, counterfeiting, or altering, or uttering what is forged counterfeited, or altered.
7. Embezzlement; fraud by a bailee, banker, agent, factor, trustee, or director or member or public officer of any company, made criminal by any law for the time being in force; or larceny.

8. Malicious injury to property if the offence be indictable.
9. Obtaining money, goods, or valuable securities by false pretences.
10. Crimes against bankruptcy law.
11. Perjury, or subornation of perjury.
12. Rape.
13. Carnal knowledge, or any attempt to have carnal knowledge, of a girl under 16 years of age.
14. Indecent assault.
15. Administering drugs, or using instruments with intent to procure the miscarriage of a woman.
16. Abduction.
17. Child stealing.
18. Kidnapping of minors and their false imprisonment.
19. Burglary or housebreaking.
20. Arson.
21. Robbery with violence.
22. Any malicious act done with intent to endanger the safety of a railway train.
23. Threats by letter or otherwise, with intent to extort.
24. Piracy by law of nations.
25. Sinking or destroying a vessel at sea, or attempting to do so.
26. Assaults on board a ship on the high seas, with intent to destroy life or do grievous bodily harm.
27. Revolt by two or more persons on board a ship on the high seas against the authority of the master.
28. Dealing in slaves in such a manner as to constitute a criminal offence against the laws of both States.

Extradition is also to be granted for participation in any of the aforesaid crimes, provided such participation be an extradition crime by the laws of the State applied to.

In the foregoing cases extradition shall take place only when the crime, if committed within the jurisdiction of the country on which the claim for surrender is made, would constitute an extradition crime by the laws of that country.

Extradition may also be granted, at the discretion of the State applied to, in respect of any other crime for which, according to the laws of both the Contracting Parties for the time being in force, the grant can be made.

III. Either Government may, in its absolute discretion, refuse to surrender its own subjects to the other Government.

IV. The extradition shall not take place if the person claimed on the part of the British Government, or the person claimed on the part of the Netherland Government, has already been tried and discharged or punished, or is actually upon his trial, within the territory of the other of the two High Contracting Parties, for the crime for which his extradition is demanded.

If the person claimed on the part of the British Government, or if the person claimed on the part of the Netherland Government, should be under examination, or is undergoing sentence under a conviction, for any other crime within the territories of the two High Contracting Parties respectively, his extradition shall be deferred until after he has been discharged, whether by acquittal, or on expiration of his sentence or otherwise.

V. The extradition shall not take place if, subsequently to the commission of the crime, or the institution of the penal prosecution, or the conviction thereon, exemption from prosecution or punishment has been acquired by lapse of time, according to the laws of the State applied to.

VI. A fugitive criminal shall not be surrendered if the offence in respect of which his surrender is demanded is one of a political character or if he prove that the requisition for his surrender has, in fact, been made with a view to try or punish him for an offence of a political character.

tion for his surrender has, in fact, been made with a view to try or punish him for an offence of a political character.

VII. A person surrendered may in no case be kept in prison, or be brought to trial in the State to which the surrender has been made, for any other crime or on account of any other matters than those for which the extradition shall have taken place, until he has been restored or had an opportunity during one month of returning to the State by which he has been surrendered.

This stipulation does not apply to crimes committed after the extradition.

VIII. The requisition for extradition shall be made through the Diplomatic Agents of the High Contracting Parties respectively.

The requisition for the extradition of an accused person must be accompanied by a warrant of arrest issued by the competent authority of the State requiring the extradition, and by such evidence as, according to the laws of the place where the accused is found, would justify his arrest if the crime had been committed there.

If the requisition relates to a person already convicted, it must be accompanied by the sentence of condemnation passed against the convicted person by the competent Court of the State that makes the requisition for extradition.

A sentence passed in contumaciam is not to be deemed a conviction, but a person so sentenced may be dealt with as an accused person.

IX. If the requisition for extradition be in accordance with the foregoing stipulations, the competent authorities of the State applied to shall proceed to the arrest of the fugitive.

X. Pending the presentation of the demand for extradition through the Diplomatic channel, a fugitive criminal may be apprehended under a warrant issued by any Police Magistrate, Justice of the Peace, or other competent authority in either country, on such information or complaint and such evidence or after such proceedings as would, in the opinion of the authority issuing the warrant, justify the issue of a warrant if the crime had been committed or the person convicted in that part of the dominions of the two Contracting Parties in which the Magistrate, Justice of the Peace, or other competent authority exercises jurisdiction: Provided however, that in the United Kingdom the accused shall, in such case, be sent as speedily as possible before a Magistrate. He shall, in accordance with this Article, be discharged, as well in the Netherlands as in the United Kingdom, if within the term of twenty days a requisition for extradition shall not have been made by the Diplomatic Agent of the demanding country in accordance with the stipulations of this Treaty. The same rule shall apply to the cases of persons accused or convicted of any of the crimes or offences specified in this Treaty and committed on the high seas on board any vessel of either country which may come into a port of the other.

XI. If the fugitive have been arrested in the British dominions, he shall forthwith be brought before a competent Magistrate, who is to examine him, and to conduct the preliminary investigation of the case, just as if the apprehension had taken place for a crime committed in the British dominions.

In the examinations which they have to make in accordance with the foregoing stipulations, the authorities of the British dominions shall admit as valid evidence depositions or statements on oath or the affirmations of witnesses taken in the Netherlands, or copies thereof, and likewise the warrants and sentences issued therein and certificates of, or judicial documents stating the fact of, a conviction, provided the same are authenticated as follows:—

1. A warrant must purport to be signed by a Judge, Magistrate, or officer of the Netherlands.
2. Depositions or affirmations, or the copies thereof, must purport to be certified under the hand of a Judge, Magistrate, or officer of the Netherlands, to

be the original depositions or affirmations, or to be the true copies thereof, as the case may require.

3. A certificate of, or judicial document stating the fact of, a conviction must purport to be certified by a Judge, Magistrate, or officer of the Netherlands.
4. In every case such warrant, deposition, affirmation, copy, certificate, or judicial document must be authenticated either by the oath of some witness, or by being sealed with the official seal of the Minister of Justice, or some other Minister of State of the Netherlands; but any other mode of authentication for the time being permitted by the law in that part of the British dominions where the examination is taken may be substituted for the foregoing.

XII. If the fugitive have been arrested in the dominions of the Netherlands, the officer of justice shall prefer a requisition within three days after the arrest, or, if the arrest have not taken place, or if it have taken place prior to the application for extradition, then within three days after the receipt of authority for that purpose from the Netherland Government in order that the person claimed may be interrogated by the Court, and that it may express its opinion as to the grant or refusal of extradition.

Within fourteen days after the interrogatory the Court shall forward its opinion and its decision, with the papers in the case, to the Minister of Justice.

The extradition shall only be granted on the production, either in original or in authenticated copy—

1. Of a conviction; or
2. (a) Of a warrant of arrest (which, by the law of the British dominions, is the only document which is granted when it is adjudged upon evidence taken on oath that the accused ought to be taken into custody), issued in the form prescribed by British Law, and indicating the offence in question sufficiently to enable the Netherland Government to decide whether it constitutes, in contemplation of Netherland Law, a case provided for by the present Treaty, and
- (b) Of the evidence.

In the examinations which they have to make in accordance with the foregoing stipulations, the authorities of the Netherland dominions shall admit as valid evidence depositions or statements on oath, or the affirmations of witnesses taken in the British dominions, or copies thereof, and likewise the warrants and sentences issued therein, and certificates of, or judicial documents stating the fact of, a conviction, provided the same are authenticated as follows :—

1. A warrant must purport to be signed by a Judge, Magistrate, or officer of the British dominions.
2. Depositions or affirmations, or the copies thereof, must purport to be certified under the hand of a Judge, Magistrate, or officer of the British dominions, to be the original depositions or affirmations, or to be true copies thereof, as the case may require.
3. A certificate of, or judicial document stating the fact of, a conviction, must purport to be certified by a Judge, Magistrate, or officer of the British dominions.
4. In every case such warrant, deposition, affirmation, copy, certificate, or judicial document must be authenticated either by the oath of some witness, or by being sealed with the official seal of one of the Principal Secretaries of State, or some other Minister of State of the British dominions; but any other mode of authentication for the time being permitted by law in that part of the dominions of the Netherlands where the examination is taken may be substituted for the foregoing.

XIII. The extradition shall not take place unless the evidence be found sufficient, according to the laws of the State

applied to, either to justify the committal of the prisoner for trial, if the crime had been committed in the territory of the said State, or to prove that the prisoner is the identical person convicted by the Courts of the State which makes the requisition, and that the crime of which he has been convicted is one in respect of which extradition could, at the time of such conviction, have been granted by the State applied to. The fugitive criminal shall not be surrendered until the expiration of fifteen days from the date of his being committed to prison to await his surrender.

XIV. If the individual claimed by one of the two High Contracting Parties in pursuance of the present Treaty should be also claimed by one or several other Powers on account of other crimes or offences committed upon their respective territories, his extradition shall be granted to that State whose demand is earliest in date.

XV. All articles seized which were in the possession of the person to be surrendered, at the time of his apprehension, shall, if the competent authority of the State applied to for the extradition has ordered the delivery thereof, be given up when the extradition takes place, and the said delivery shall extend not merely to the stolen articles, but to everything that may serve as a proof of the crime.

XVI. The respective Governments mutually renounce all claim for the repayment of expenses incurred by them in the arrest and maintenance and transport of the person to be surrendered, and all other expenses which may be incurred within the limits of their respective territories until the person to be surrendered is placed on board ship, together with the expenses of giving up and returning all seized articles and of sending and returning the papers containing proof of the crime or other document and they reciprocally agree to bear all such expenses themselves.

The above stipulations, however, shall not apply to extradition to and from Canada, as regards which Colony all the expenses shall be borne by the demanding State.

The person to be extradited shall be sent to the port which the Diplomatic or Consular Agent of the demanding State shall indicate.

XVII. If in any criminal matter pending in any Court or Tribunal of one of the two countries it is thought desirable to take the evidence of any witness in the other, such evidence may be taken by the judicial authorities in accordance with the laws in force on this subject in the Country where the witness may be; and any expenses incurred in taking such evidence shall be defrayed by the country in which it is taken.

XVIII. The stipulations of the present Treaty shall apply to the Colonies and foreign possessions of the two High Contracting Parties, but being based upon the legislation of the mother country, shall only be observed on either side so far as they may be compatible with the laws in force in those Colonies or possessions.

The demand for the extradition of an offender who has taken refuge in a Colony or foreign possession of either Contracting Party may also be made directly to the Governor or principal functionary of that Colony or possession by the Governor or principal functionary of a Colony or possession of the other Contracting Party when the two Colonies or foreign possessions are situated in Asia, Australia (including New Zealand and Tasmania), the Pacific and Indian Oceans, or South or East Africa.

The same rule shall be followed if the two Colonies or foreign possession are situated in America (including the West India Islands). The said Governors or principal functionaries shall have the power either of granting the extradition or of referring the question to their Government.

In all other cases, the demand for extradition shall be made through the diplomatic channel.

The period of provisional arrest provided for in Article X shall for the purposes of this Article be extended to sixty days.

XIX. From the day when the present Treaty shall come into force the Treaty of Extradition between the two countries of the 19th June, 1874 shall cease to have effect; but the present Treaty shall apply to all crimes within the Treaty, whether committed before or after the day when it comes into force.

XX. The present Treaty shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged as soon as possible.

The Treaty shall come into force three months after the exchange of the ratifications. It may be terminated by either of the High Contracting Parties at any time on giving to the other six months notice of its intention to do so.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seal of their arms.

Done in duplicate, at London, this 26th day of September, 1898."

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to Netherlands on and from the date of publication of this order.

[No. L/413/13/88]

DR. P. SREENIVASA RAO, Director (L&T)

